भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 673
गुरुवार, 6 फ़रवरी, 2025/17 माघ, 1946 (शक), को दिया जाने वाला उत्तर

पचास अतिरिक्त विमानपत्तनों का विकास

673. श्री शशांक मणिः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का आगामी पांच वर्षों में पचास अतिरिक्त विमानपत्तन विकसित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त पहल का उद्देश्य देश में विमानपत्तन ईको सिस्टम को किस प्रकार प्रोत्साहन देना है; और

(ग) क्या विमानपत्तन नेटवर्क के विस्तार से विमानन क्षेत्र में रोजगार सृजन और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की आशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): नागर विमानन मंत्रालय ने जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा को किफ़ायती बनाने के लिए देश में असेवित एवं अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की है। 1000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ, तीन वर्ष की अवधि, अर्थात 01.04.2023 से 31.03.2026 के दौरान भारत सरकार ने 50 से अधिक असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/ हेलीपैडों/ वॉटर एयरोड्रोमों और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड (एएलजी) के जीर्णोद्धार/ विकास के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ग): हवाईअड्डे आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभर कर आए हैं तथा राष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था पर इसका प्रवर्धक प्रभाव पड़ता है। नागर विमानन क्षेत्र एवं आर्थिक विकास के बीच के संबंध सर्वमान्य हैं। हवाईअड्डों के विकास से यात्रियों की आवाजाही में वृद्धि होती है, पर्यटन का विकास होता है, रोजगार का सृजन होता है तथा भूमि की कीमतों के सर्किल रेट में वृद्धि होती है, जिससे संबंधित राज्य में विभिन्न करों/ स्टांप शुल्कों, आदि के संग्रह में बढ़ोतरी होती है, तथा देश का समग्र विकास होता है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) के अध्ययन से पता चलता है कि हवाई संपर्क का आर्थिक प्रवर्धन 3.25 और रोजगार प्रवर्धन 6.1 है।

****